...'इस' बार न 'टूटे' न 'बिके' और न ही 'झुके'

पहली बार बागी जिला पंचायत सदस्यों ने दिखाई एकता, हवाई अड्डा होटल में जमे रहे, 43 में से 29 जिला पंचायत सदस्यों ने दी अध्यक्ष का पहली बार पटकनी

तेजयुग न्यूज

बस्ती।...जिस पार्टी के सांसद, विधायक और प्रमुख अपने जिला पंचायत अध्यक्ष के सबसे कठिन परीक्षा में साथ छोड़ देगें, तो जाहिर सी बात है, कि बदनामी और हार दोनों होगी ही। षनिवार को जिस तरह कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक नहीं हो सकी, उसके लिए अध्यक्ष को कम और पार्टी और माननीयों को अधिक जिम्मेदार माना जा रहा है।

❖ सबसे अधिक परेशानी जिला पंचायत के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को होगी ❖ 29 सदस्यों में से चार सदस्यों ने बाहर से विरोध जताते हुए समर्थन दिया ❖ 25 सदस्यों ने रामजी का फोटो लेकर गददारी न करने की कसम खाई, वीडियो बना

❖ जिसे अध्यक्ष अपना मानते थे, उन्होंने ने भी दिया धोखा, भाजपा के सांसद और विधायक ने भी नहीं दिया साथ
❖ सपा के तीनों विधायकों ने दिया साथ, अपनों के बीच बेगाने हो गए अध्यक्ष
❖ बैठक का कोरम पूरा न होने से गहराया वित्तीय संकट

कहा भी जा रहा है, कि जहां पर पार्टी के मान-सम्मान की आ जाए तो वहां सारे गिलवे षिकवे भूल कर पार्टी से जुड़े लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर, सत्ता पक्ष के प्रथम नागरिक, के लिए 22 सदस्य नहीं जुटा पाते तो इसे सत्ता और पार्टी की हार मानी जाएगी। ऐसा लगता है, कि मानो सभी को इसी दिन का इंतजार था, इसी लिए यह लोग न तो बैठक में आए और न कोरम को पूरा कराने में कोई सहयोग किया। पार्टी के लोगों ने तो अध्यक्ष का साथ तो नहीं दिया, अलबत्ता सपा के तीनों विधायकों ने अवष्य दिया। अध्यक्ष ने जिन्हें मालामाल किया, उन लोगों ने भी ऐसे समय में साथ छोड़ दिया। सिर्फ साथ ही नहीं छोड़ा अलबत्ता 29 सदस्यों को सजोए भी रखा। पिछले तीन सालों में अध्यक्ष की यह पहली हार है, इस हार के कई मायने निकाले जा रहे है, कहा जा रहा हैं, कि अगर सदस्यों को उनके इच्छानुसार पांच-पांच लाख मिल गया होता तो षायद अध्यक्ष को यह दिन न देखना पड़ता।

हालांकि पांच लाख देने का निर्णय तो हुआ, मगर देर से हुआ। इस जीत से विरोधी खेमा बहुत खुष हैं, और कह रहा है, कि पिक्चर अभी बाकी है, पूरा पिक्चर चुनाव के बाद दिखाया जाएगा। 29 सदस्यों में छह महिला सदस्य भी षामिल रही। सबसे बड़ी समस्या जिला का विकास तो बाधित होगा ही, साथ ही जिला पंचायत के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। इनमें कई तो ऐसे हैं, जो हर माह लिए गए लोन की ईएमआई भरते है। 24-25 का बजट पारित न होने से अब इन लोगों को वेतन जून में ही मिलेगा। तब तक इन्हें परिवार का भरण-पोषण और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। हालांकि अध्यक्ष ने इन सभी को भरोसा दिलाया है, कि उनके रहते किसी भी कर्मचारी के परिवार का भरण-पोषण का सामना करने की नौबत नहीं आएगी। वैसे भी यह अपने कर्मियों को पूरा ख्याल रखते हैं। ईलाज से लेकर अन्य जरुरत को भी पूरा करते रहतें है। यह इनकी एक अच्छाई है।

बोर्ड की बैठक षुरु होते ही यह लगने लगा था, कि इसबार अध्यक्ष का लालीपाप देने वाला फारमूला कामयाब नहीं होगा, यह बातें जब कर्मियों की ओर से कही जाने लगी तो सच्चाई नजर आई। इन कर्मियों को सबसे बड़ी चिंता बैठक स्थगित होने से होने वाली परेषानी और समस्याओं को लेकर थी। बहरहाल, जब एक बजे तक माननीयों और सदस्यों की कुर्सी खाली रही तो लगने लगा कि पहली बार कोरम के अभाव में बैठक नहीं होगा। हालांकि कि उसके बाद सपा के तीनों विधायक एक साथ आए, मगर भी लौट गए। जो पार्टी के माननीय कभी अध्यक्ष का बचाव करने के लिए लखनउ से भागे-भागे चले आते थे, आज वह जिले में रहते हुए भी नहीं आए। वहीं कोरम पूरा न होने से गदगद नजर आए बागी सदस्यों ने कहा कि इस बार अध्यक्ष न तो सदस्यों को तोड़ पाए, न खरीद पाए और न झुका ही पाए। कहते हैं, कि इसके लिए सदस्य कई दिनों से पटकनी देने की रणनीति बना रहे थे, जिसे उन्होंने षनिवार को विजई के रुप में अंजाम दिया। यह लोग टोल प्लाजा के पास अनूप खरे के हवाई अडडा होटल में जीत का इंतजार करते रहे, और जीत के बाद जष्न भी मनाया गया, और कहा गया, कि अध्यक्षजी को इस तरह की हार के लिए आगे भी तैयार रहना होगा। अध्यक्ष के खेमे के लोगों का कहना है, कि अध्यक्षजी को अपनी रणनीति में बदलाव लाना चाहिए। क्यों कि सदस्यों को अधिक दिन तक लालीपाप नहीं दिया जा सकता है।

इस जीत के बाद कहना गलत नहीं होगा कि बागी सदस्यों को आगे की लड़ाई लड़ने के लिए एक नई उर्जा मिली है। कई सदस्यों ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव के बाद अध्यक्ष को अपनी कुर्सी बचाना मुस्किल हो जाएगा। हालांकि बिकने वाले सदस्यों पर बहुत अधिक भरोसा उनके साथी ही नहीं कर रहें है। यह भी सही है, कि अगर अध्यक्ष से चूक नहीं हुई होती तो आज बागियों को जष्न मनाने का मौका नहीं मिलता। इस घटना के बाद सदस्यों की कीमत बढ़ गई हैं, अब यह लोग बड़ी रकम के लिए मुसीबत के दिनों में ब्लैक मेल कर सकते है। बैठक के दो घंटा पहले तक अध्यक्ष का खेमा 30 सदस्यों के साथ होने का दावा कर रहा था। बहरहाल, अपरिहार्य कारणों से बैठक को स्थगित करने की घोषणा की गई। सवाल उठ रहा है, कि अब उन दो-दो लाख का क्या होगा, जो सदस्यों के खाते में भेजा गया? क्या सदस्य ईमानदारी दिखाते हुए पैसा वापस करेगें? या फिर न्यौता हकारी के लिए रख लेंगे। खास बात यह रही कि 29 सदस्यों में से चार सदस्यों ने बाहर से विरोध जताते हुए समर्थन दिया। यह लोग जिले में नहीं थे।

इनमें कई नामचीन लोग भी षामिल है। जीत के बाद उपस्थित 25 सदस्यों ने रामजी का फोटो लेकर गददारी न करने की कसम खाई, और कहा कि यही 29 सदस्य जैसा चाहेंगे जिला पंचायत को चलाएगें। कसम खाने वाला वीडियो भी बनाकर रखा गया, और यह कहा गया कि अगर भविष्य में जो कोई गददारी करेगा, उसी समय रामजी का फोटो वायरल कर दिया जाएगा। अध्यक्ष के खेमे के लोगों का कहना है, कि लोग अध्यक्षजी को ब्लैक मेल करने पर उतारु हो गए थे, इसी लिए अध्यक्षजी ने बैठक को स्थगित कर दिया, ताकि ब्लैक मेल होने से बचा जा सके।

...कैसे होगें 'रोजगार सेवक' ईमानदार, जब 'बीडीओ' ही 'बेइमान' बनाने पर 'तुले'

बनकटी में रोजगार सेवक के जेल जाने से सहमें, अन्य रोजगार सेवक

तेजयुग न्यूज

बस्ती।...इसे बनकटी ब्लॉक के लोगों का दुभार्ग्य कहें या फिर भ्रष्टाचार। इस ब्लॉक को अभी तक जितने भी बीडीओ मिले लगभग सभी ने भ्रष्टाचार का रिकार्ड बनाया। इस ब्लॉक के रोजगार सेवक अगर ईमानदारी दिखाना चाहते भी हैं, तो यहकर चुप करा दिया जाता है, कि अगर अधिक ईमानदारी दिखाने का प्रयास किया तो मुसीबत में आ जाओगे, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अधिकांश रोजगार सेवक चाहते हैं, कि वह उन्हीं मजदूरों की हाजीरी लगाएं, जो काम कर रहें है। लेकिन बीडीओ साहब यह नहीं चाहते कि कोई रोजगार सेवक ईमानदारी से काम करें।

अब सवाल उठ रहा है, ऐसे में फर्जीवाड़े पर रोक लगेगा तो कैसे? जब मेढ़ ही खेत खाने लगेगा। आमकोईल के रोजगार सेवक के जेल जाने के बाद लगभग सभी रोजगार सेवक डरे हुए से नजर आ रहे है। इसी को लेकर एक दिन पहले 40 से अधिक रोजगार सेवक ब्लॉक के हाल में चर्चा कर रहे थे, कि अब हम लोग फर्जी मजदूरों की हाजीरी नहीं लगाएंगें, क्यों कि जेल न तो प्रधान जाता है, और न सचिव और न बीडीओ ही। चर्चा हो ही रही थी कि इसी बीच भाजपा के बड़े नेता पहुंच गए, और उन्होंने भी रोजगार सेवकों के निर्णय पर सहमति जताया, इसी बीच बीडीओ आ गए, और जब उनके सामने यह बात रोजगार सेवकों ने रखी तो वह आगबबूला हो गए, और कहने लगे, कि अगर आप लोगों ने ईमानदारी दिखाई और प्रधानों के कहे नुसार नहीं चले और फर्जी हाजीरी नहीं लगाया तो मुसिबत में पड़ जाओंगे, बड़ा नुकसान भी हो सकता है।

बीडीओ साहब को यह नहीं मालूम कि उनकी बात कोई रोजगार सेवक रिकार्ड भी कर रहा है। यह उस बीडीओ का चरित्र है, जिसे सरकार ने पूरे ब्लॉक की जिम्मेदारी सौंपी हैं। हालांकि जिले के यह पहले ऐसे बीडीओ नहीं हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के बजाए उसे बढ़ावा दिया, इससे पहले दुबौलिया, कुदरहा और कप्तानगंज के बीडीओ इस तरह की मंशा जाहिर कर चुके है। बनकटी के एक रोजगार सेवक बीडीओ साहब से यह कहा कि साहब लोग जांच करने आते हैं, तो हम्ही लोग ही फंसेगें, इस पर बीडीओ ने मादी की तरह गांरटी दिया कि जब तक मैं हूं कोई जांच नहीं जाएगें, मैं भी नहीं जाउगां, मगर आप लोगों को वहीं करना होगा, जो प्रधान कहेगें प्रधान के कहने का मतलब आप समझ गएं होगें, कि वह क्या चाहते है।

यूंहीं अधिकांश रोजगार सेवक नाराज थे, इन लोगों का कहना है, कि प्रधान लोग उनका भी बखरा अपने पास रख लेते हैं, जब कि वह हम्हीं से फर्जीवाड़ा करवाते है। इन लोगों को उन रोजगार सेवकों से भी जलन हैं, जो धडल्ले से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, और पांच के स्थान पर दस फीसद बखरा लेते है। जो रोजगार सेवक दस फीसद बखरा लेतें हैं, वही चर्चा में भाग लेने नहीं आए थे। ऐसे ही घुघसा के रोजगार सेवक हैं, राजेष चैधरी है, जब गांव के एक व्यक्ति ने इनसे पूछा कि मौके पर 30 मजदूर काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों 280 मजदूरों की हाजीरी लगा रहें हैं, मनबढ़ रोजगार सेवक ने भददी-भददी गाली देते हुए कहा कि भाग यहां से जाओ चाहे शिकायत करों, मेरा कुछ नहीं होगा, क्यों कि बीडीओ साहब हमारे साथ है।

❖ ब्लॉक में इस बात पर चर्चा हो रही थी, कि हम लोग उतने ही मजदूरों की हाजीरी लगाएगें, जो सही होगा
❖ कहा कि सारा मलाई प्रधान और ब्लॉक वाले खा जाते हैं, और जेल उन्हें जाना पड़ता
❖ लगभग 40 से अधिक रोजगार सेवकों ने जब ईमानदारी दिखाने की बात कही तो बीडीओ ने कहा कि प्रधान जैसा चाहते हैं, वैसा करों, वरना नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता
❖ इस बात पर भी चर्चा हुई कि जब उनका बखरा भी नहीं मिलता तो वह क्यों जेल जाएं
❖ हालांकि ब्लॉक के एक जिम्मेदार भाजपा नेता ने रोजगार सेवकों का समर्थन किया, मगर, बीडीओ के सामने उनकी एक न चली

तेजयुग फॉलोअप खबर

...आखिर 'अधिकारी' क्यों 'तीसरे स्थान' पर आने का 'जश्न' मना 'रहे'?

आखिर क्यों 96.5 फीसदी मजदूर सौ दिन का रोजगार पाने से वंचित रह गए

तेजयुग न्यूज

बस्ती।...अगर जिले में साढ़े तीन अरब खर्च करने के बाद मात्र साढ़े तीन फीसद मनरेगा श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार मिलता है, और उसके बाद भी जिला प्रदेश में तीसरे पायदान पर पहुंचता है, तो हैं न हैरानी वाली बात। सवाल उठ रहा है, कि अधिकारी इस बात का जश्न क्यों मना रहे हैं, कि जिला तीसरे स्थान पर आ गया, इस बात का मंथन क्यों नहीं कर रहे हैं, जहां 100 फीसद आना चाहिए, वहां साढ़े तीन फीसद क्यों आया? इसे जिले की उपलब्धि मानी जाए या फिर नाकामी, यह जांच का विषय है।

यह भी मंथन और जांच का विषय है, कि क्यों सौ दिन का रोजगार पाने से 96.50 फीसद रोजगार वंचित रह गए। यह भी सोचना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जो सबसे अधिक काम करती है, और सबसे अधिक घर में मौजूद रहती है, उन्हें क्यों नहीं पुरुषों के मुकाबले 100 दिन का अधिक रोजगार मिला? यहां तक कि एससी वर्ग जिनके परिवार की संख्या 51565 हैं, और जिन्हें सबसे अधिक रोजगार की आवष्यकता है, उन्हें भी मात्र 3.08 फीसद ही सौ दिन का रोजगार मिला। यही कारण है, कि सौ दिन का रोजगार देने वाली इस गांरटी योजना पर सवाल उठ रहा है।

सोचने वाली बात यह है, कि जहां हर मजदूर को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, वहां मात्र 3.59 फीसद मजदूरों को ही सौ दिन का रोजगार मिला। जबकि वित्तीय साल समाप्त होने के कगार पर हैं, अब सवाल खड़ा हो रहा है, कि यह जिले की उपलब्धि मानी जाए या नाकामी, मात्र 3.59 फीसद की उपलब्धि को कैसे संतोषजनक समझा जाए? जबकि 96.50 फीसद मजदूरों को सौ दिन का रोजगार ही नहीं मिल पाया। लगभग 40 फीसद ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जो एक भी मजदूर परिवार को सौ दिन का रोजगार नहीं उपलब्ध करा पाई, जबकि रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहे। 1185 ग्राम पंचायत वाले इस जिले में एक भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं जो 30 फीसद मजदूरों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करा पाई।

अब आ जाइए, एससी वर्ग के श्रमिकों पर। 51565 परिवार में से मात्र 3564 परिवार को ही सौ दिन का रोजगार मिला। यानि 3.08 फीसद को ही सौ दिन का रोजगार मिला। पुरुषों के बराबर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का दावा करने वाली सरकार यहां महिलाओं को भी रोजगार देने में पीछे रही। जबकि सबसे अधिक उपलब्धता महिलाओं की ही रहती हैं। पुरुष तो कामकाज को लेकर अक्सर बाहर ही रहते है। इस योजना में घर पर रहने वाली महिलाएं ही रोजगार पाने में पीछे है। ऐसे में भला मनरेगा रोजगार का ग्राफ कैसे उपर होगा। हर व्यक्ति को योजना के अनुसार रोजगार मिले इसके लिए सरकार और जिम्मेदारों को आबादी के अनुसार ही जॉब कार्ड सुनिष्चित करना चाहिए। रोजगार के अवसर भी उसी के अनुसार उपलब्ध कराना चाहिए। ताकि हर व्यक्ति को सौ दिन का रोजगार मिल सके, और यह योजना धरातल पर दिखाई देने के साथ मजदूरों के पलायन को भी रोका जा सके। लेकिन यहां पर तो उंट के मुंह में जीरा जैसी स्थित है।

❖ अधिकारी इस बात का मंथन क्यों नहीं कर रहे हैं, कि साढ़े तीन अरब खर्च करने के बाद भी क्यों साढ़े तीन फीसद मजदूरों को ही सौ दिन का रोजगार मिला ❖ इसे जिले की उपलब्धि मानी जाए या फिर नाकामी, कि जहां 100 फीसद मजदूरों को सौ दिन का रोजगार मिलना चाहिए, वहां मात्र साढ़े तीन फीसद ही मिला ❖ जो महिला सबसे अधिक का भी करती है, और घर पर भी रहती, उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम रोजगार मिला ❖ सबसे गरीब परिवार एससी वर्ग के परिवार को भी तीन फीसद 100 दिन का रोजगार मिला

तेजयुग फॉलोअप खबर

आमने-सामने से भिंडी बाइक

ऊंचाहार। दो बाइकों के बीच आमने सामने से हुई जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार तीन लोग घायल हो गये, जिन्हें राहगीरों की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मामला नगर के खरौली रोड का है, जहां शुक्रवार की दोपहर दो बाइकों के बीच आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई, घटना में एक बाइक पर सवार विक्रम 17 वर्ष, व दिव्यांश 16 वर्ष निवासी पूरे जिल्ला मजरे गंगौली तथा दूसरे बाइक पर सवार कासिफ 30 वर्ष निवासी रेलवे कॉलोनी घायल हो गये, राहगीरों की मदद से घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

चेयरपर्सन 'नेहा वर्मा' ने प्रस्तुत किया पहला 'बजट'

92.12 करोड़ से नगर पालिका को 24-25 में विकास करने की बनी योजना

❖ जल निगम बस्ती से बडेवन से कम्पनी बाग तक पाइप लाइन को ठीक कराने हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही करने पर विचार किया गया

तेजयुग न्यूज

बस्ती। नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन नेहा वर्मा ने बोर्ड के सामने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया। बैठक में पालिका के 24 सभासदों, सदस्यगणों ने हिस्सा लिया। बैठक में नगर पालिका परिषद के वित्तीय वर्ष 2024-25 का संतुलित अनुमानित बजट रूपया 92,12.72, 851.00 (बानवे करोड बारह लाख बहत्तर हजार आठ सौ इक्यावन) आय एवं रूपया 92.09.92.564.00 (बानवे करोड नौ लाख इक्यावन हजार पाच सौ चैसठ) के व्यय तथा रूपया 2,80,287.00 (दो लाख अस्सी हजार दो सौ सतासी) बचत प्रस्तावित किया गया जिसे ध्वनि मत से मेज थपथपा कर सर्व सम्मत से स्वीकृत किया गया।

नगर के विकास हेतु सभासदो द्वारा प्रस्ताव किया गया जिसे सदन ने ध्वनिमत से पास किया। इसी क्रम में जल निगम बस्ती से बडेवन से कम्पनी बाग तक पाइप लाइन को ठीक कराने हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही करने पर विचार किया गया। सदन में सभासदगणों द्वारा अपने वार्ड से सम्बन्धित समस्याओं तथा विकास कार्यों को सदन के पटल पर रखा गया जिसे सदन द्वारा स्वीकार किया गया। नेहा वर्मा ने कहा कि पालिका क्षेत्र के विकास के लिये परस्पर समन्वय से कार्य करना होगा जिससे नागरिकों को बेहतर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, और जलापूर्ति की बेहतर सेवा प्राप्त हो। इस दिशा में निरन्तर तेजी के साथ प्रयास किये जा रहे हैं। अधिशासी अधिकारी/उपजिलाधिकारी (न्यायिक) सतेन्द्र सिंह ने योजनाओं के सम्बन्ध में सदस्यों को विन्दुवार विस्तार से जानकारी दिया।

बैठक में अमरावती देवी, राजन ठाकुर, इन्द्रावती देवी, श्रीमती रोली, विद्यावती देवी, ममता सोनकर, रविन्द्र कुमार, मु0 अय्यूब, दिनेश गुप्ता, निर्मला देवी, मंजू श्रीवास्तवा, निर्मला यादव, पंकज कुमार चैधरी, श्रीमती बैजन्ती सिंह, कृष्ण कुमार पाण्डेय, सर्वेश यादव, जगदीप श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार चैधरी, रूकइया खातून, गौतम यादव, प्रफुल्ल श्रीवास्तव, परमेश्वर कुमार शुक्ला उर्फ पप्पू शुक्ला, श्रीमती शाहजहाँ, रमेश कुमार गुप्ता, कर निर्धारण अधिकारी उदयभान, अवर अभियन्ता जल अर्चना कुमारी, लेखाकार गणेश कुमार सिंह, सम्पत्ति लिपिक गिरीश कुमार सिंह, प्रकाश प्रभारी अमित कुमार शुक्ला, स्टोर कीपर शुभम यादव सदन लिपिक राजीव शंकर श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

किसान नेता 'चंद्रेश प्रताप सिंह' ने 'पीसीएफ' के 'भ्रष्टाचार' पर साधा 'निशाना', केस दर्ज की मांग

तेजयुग न्यूज

बस्ती।..धान/गेहूं की सबसे बड़ी खरीद एजेंसी के अधिकारियों और इनके केंद्र प्रभारियों के भ्रष्टाचार की परत-दर-परत खुलती जा रही है। जिस तरह पीसीएफ के डीएस ने जिले में भ्रष्टाचार किया है, उससे सरकार के धान/गेहूं क्रय नीति को बहुत बड़ा झटका लगा है। इन्होंने न सिर्फ क्रय नीति को बर्बाद किया, बल्कि सरकार का करोड़ों रुपया बर्बाद किया। बार-बार सवाल उठ रहा है, कि आखिर पीसीएफ के डीएस इतने सालों से क्यों बस्ती में जमे हुए है?

जबकि इनके उपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुएं है। इससे पता चलता है, कि इस विभाग में भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला हैं, जहां पर चाहे जितना सरकारी धन का गबन करो, चाहें जितना सीएमआर का नुकसान करो, सब माफ है। इसी पीसीएफ की

❖❖ कमिश्नर को लिखे पत्र में कहा कि अगर पीसीएफ के डीएस और इनके केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं तो किसान आंदोलन करेगा ❖❖ फर्जी धान खरीद करने वाले पीसीएफ के अधिकारियों और केंद्र प्रभारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की

देन हैं, कि मंडल के 155 राइस मिलर्स के द्वारा 2011 से 47 करोड़ का सीएमआर गबन कर लिया गया, इतना बड़ा गबन हुआ, मगर अधिकारी और केंद्र प्रभारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब भी कार्रवाई की बारी आती है, यह सबका मुंह पैसे से बंद कर देते है। भाकियू भानू गुट के मंडल प्रवक्ता चंदेष प्रताप सिंह ने कमिश्नर को पत्र लिखकर पीसीएफ के भ्रष्टाचार की जांच कराने और पीसीएफ के डीएस और इनके केंद्र प्रभारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। इनके चलते सरकार की छवि धूमिल हो रही है, और किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा।

लिखे पत्र में कहा गया है, कि मंडल में इनके जितने भी धान क्रय केंद्र हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, क्यों कि सबसे अधिक फर्जी धान की खरीद इन्ही के ही सेंटरों पर हुई। जिन किसानों से इन्होंने धान खरीदा उनका मोबाइल और आधार नंबर नहीं लिया, किसानों का पता तक नहीं लिखा। लिखा कि रामनगर ब्लॉक के बढ़या लाल सिंह के केंद्र प्रभारी विनोद ने अपने और पिता सहित परिवार की महिला के नाम से 300 क्विंटल फर्जी धान खरीद लिया। इस केंद्र पर बड़े पैमाने में फर्जी खरीद की गई। अधिकांष खरीद दलालों और बिचैलियों से खरीदे गए। इसी तरह जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियांगज स्थित औसान कुईया केंद्र पर बड़े पैमाने पर फर्जी खरीद हुई। कमिष्नर से मंडलीय टीम गठित कर जांच कराने की मांग की गई।